

विहगावलोकन

2003-04 के दौरान गतिविधियां

1.1 वर्ष 2003-04 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र कार्य-निष्पादन की विशेषता थी - 8.2 प्रतिशत की उच्च वास्तविक सदेउ की वृद्धि दर, - जो गत 15 वर्षों में उच्चतम वृद्धि दर रही है और साथ ही यह चीन के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च वृद्धि दर है। सदेउ में यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में आये बदलाव के कारण थी, व्यापक आधार वाली औद्योगिक वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र में निरन्तर जारी रही भारी वृद्धि ने भी इसमें सहायता की। मुद्रास्फीति की स्थिति वर्ष के दौरान कमोवेश स्थिर बनी रही। वर्ष 2003-04 के लिए केन्द्र का संशोधित राजकोषीय घाटा सकल देशी उत्पाद के 4.8 प्रतिशत पर रहा जो बजट में अनुमानित स्तर से 0.8 प्रतिशत न्यूनतर था। निर्यातों, संविभागीय निवेशों और अदृश्य प्राप्तियों में निरन्तर बनी रही तेज वृद्धि के कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आगमों ने भुगतान संतुलन की स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान किया जो भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च 2004 के अंत तक बढ़कर 113 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच जाने में झलकता है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, वित्तीय क्षेत्र ने स्थिर और सहज स्थितियां दर्शायीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण के उठाव में 2003-04 के उत्तरार्द्ध में तेजी देखी गयी, जो औद्योगिक वृद्धि में आये पुनः उछाल के अनुरूप थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याजेतर आय ने भी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शायी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने आकर्षक जोखिम-मुक्त आय की दृष्टि से निर्धारित अपेक्षाओं से अधिक भारी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों को रखना जारी रखा और उनकी आय की स्थिति मुख्यतः कोषागार परिचालनों से प्रेरित बनी रही। अन्य बातों के साथ-साथ हाल ही में बने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 के अधिनियम बन जाने से प्रेरित बेहतर वसूली प्रयासों तथा बेहतर जोखिम प्रबन्ध प्रणालियों जैसी विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप अग्रिमों के प्रति गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आयी।

1.2 सहकारी बैंकों ने जमाराशियों और अग्रिमों में उच्चतर वृद्धि दर्ज की तथा आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता दोनों में कुछ सुधार दर्शाया। विकास वित्त संस्थाओं द्वारा स्वीकृतियों और संवितरणों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्य-निष्पादन में भी सुधार हुआ। रिज़र्व बैंक ने अपविनियमन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, विवेकसम्मत मानदण्डों को कड़ा करने तथा

विनियामक एवं पर्यवेक्षी निरीक्षणों में और सुधार लाने सम्बन्धी अनेक उपायों के माध्यम से 2003-04 के दौरान वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को आगे बढ़ाया।

व्यापक परिवेश

1.3 वर्ष 2003-04 के लिए 8.2 प्रतिशत पर समग्र वास्तविक सदेउ की वृद्धि 2002-03 में देखी गयी 4.0 प्रतिशत की वृद्धि से काफी उच्चतर रही, जो मुख्यतः 2002-03 के सूखे की स्थिति में हुए सुधार के फलस्वरूप 9.0 प्रतिशत से अधिक की कृषि से संबंधित सदेउ में आयी तेजी के कारण थी। औद्योगिक उत्पादन ने औद्योगिक उत्पादन के सभी प्रमुख घटकों में व्यापक आधार वाले अपने औद्योगिक उत्पादन के विस्तार को जारी रखा जिसने 6.0 प्रतिशत से अधिक की दर दर्शायी। 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र ने इस प्रवृत्ति से ऊपर वृद्धि को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा तथा 2003-04 की चारों तिमाहियों में 7.0 प्रतिशत से उच्च स्तर की वृद्धि दर लगातार बनाये रखी। वार्षिक मुद्रास्फीति की दर (बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक) जो मई 2003 के पहले सप्ताह में 6.9 प्रतिशत पर थी, 23 अगस्त 2003 तक गिरते हुए 3.8 प्रतिशत रह गयी। तथापि बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों, और इस्पात मूल्यों, तथा घरेलू मुद्रास्फीति पर उसके परिणामी प्रभावों के साथ-साथ फलों, खाद्य तेल और सूती वस्त्रोद्योग के मूल्यों में वृद्धि ने थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति को 1 जनवरी 2004 तक बढ़ा कर 6.6 प्रतिशत कर दिया। तथापि, मुद्रास्फीति की दर मार्च 2004 के अंत तक गिरकर 4.6 प्रतिशत पर आ गयी। इसके होते हुए भी वर्ष 2003-04 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए औसत आधार पर मुद्रास्फीति की दर (थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से) 2002-03 में दर्ज 3.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की तुलना में 5.4 प्रतिशत पर दो प्रतिशत बिंदु उच्चतर थी।

1.4 वणिक निर्यातों और सेवाओं में तेज वृद्धि, भारी पूंजी आगम और विदेशी मुद्रा का रिकार्ड भण्डार - ये 2003-04 में बाह्य क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं थीं। चालू खाता शेष सदेउ का 1.4 प्रतिशत लगातार तीसरे वर्ष भी बना रहा। प्रत्यक्ष और संविभागीय ये दोनों प्रकार के विदेशी निवेश, जोकि मुख्यतः गैर-ऋण सर्जक स्वरूप के आगम हैं, अब तक की अवधि में सर्वाधिक रूप से बढ़कर सदेउ के 3.0 प्रतिशत जितने उच्च स्तर पर आ गये। भारत ने कोरिया के बाद एशिया में सबसे ज्यादा संविभागीय निवेश को आकर्षित किया। इन गतिविधियों

का परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में 36.9 बिलियन अमरीकी डालर का रिकार्ड संचयन हुआ जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च 2004 के अंत में 113 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया - जो विश्व में छठा सबसे बड़ा भण्डार है।

1.5 चलनिधि की स्थितियां वर्ष के दौरान सहज बनी रहीं। व्यापक मुद्रा (एम₃) में वृद्धि 2002-03 की 12.7 प्रतिशत (विलियन के प्रभाव को घटाकर) की वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 16.6 प्रतिशत की रही। यह 14.0 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से ज्यादा थी। यह भारी मौद्रिक विस्तार, अक्टूबर 2003 में रिसर्जेंट इण्डिया बांड की भारी एकमुश्त चुकौती के बावजूद हुआ। घरेलू ऋण में भारी गिरावट आयी जिसका कारण खाद्य ऋण में गिरावट का आना था, यह गिरावट निम्नतर खाद्यान्न भण्डार तथा निरन्तर उच्चतर निकासी के कारण थी। तथापि, वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में 2003-04 के उत्तरार्द्ध में निरन्तर वृद्धि हुई जो औद्योगिक उत्पादन में आयी तेजी को दर्शाती है। बैंकेतर संस्थाओं से संसाधनों का प्रवाह, साथ ही, ग्लोबल डिपाजिटरी रसीद (जीडीआर), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और वाणिज्यिक पत्रों ने संसाधनों के प्रवाह को बेहतर बनाये रखा, हालांकि बैंक ऋण की तुलना में यह मामूली-सा रहा।

1.6 भारत औसत मांग मुद्रा दरें मार्च 2003 के 5.86 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में 4.37 प्रतिशत रह गयीं। इसी प्रकार, 91 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों पर अधिकतम आय भी मार्च 2003 के 5.89 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में क्रमशः 4.38 प्रतिशत और 4.45 प्रतिशत रह गयी। 61 दिवसीय से 90 दिवसीय परिपक्वतावाले वाणिज्यिक पत्रों पर भारत औसत बड़ा दर मार्च 2003 के 6.53 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में 5.19 प्रतिशत रह गयी। 3.7 प्रतिशत पर बाजार रिपो दर अप्रैल 2004 में रातभर के लिए मांग मुद्रा दर से निम्नतर थी। 5 वर्षीय और 10 वर्षीय अवशिष्ट मीयादवाली सरकारी प्रतिभूतियों पर आय मार्च 2003 के क्रमशः 5.92 और 6.21 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 में क्रमशः 4.78 और 5.15 प्रतिशत रह गयी।

1.7 एक वर्ष तक की मीयाद वाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों पर मीयादी जमा दरें मार्च 2003 के 4.00 - 6.00 प्रतिशत के दायरे से गिरकर अप्रैल 2004 तक 3.75 - 5.25 प्रतिशत के दायरे में रह गयीं। इसी प्रकार, एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें इसी अवधि के दौरान 5.25 - 7.00 प्रतिशत के दायरे से गिरकर 5.00 - 5.75 प्रतिशत के दायरे में रह गयीं। कुल मिलाकर, पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा दरों की मीयादी संरचना में काफी सपाटपन आया है।

1.8 जमा दरों में गिरावट आने और निधियों की लागतों में कमी होने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मूल उधार दरों का दायरा लगभग स्थिर बना रहा। मूल उधार दरों में निम्नमुखी स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बेंच मार्क मूल उधार दर की योजना बैंकों की उधार दरों में पारदर्शिता लाने तथा ऋणों के मूल्य-निर्धारण में निहित जटिलता को घटाने की आवश्यकता से निपटने के लिए अप्रैल 2003 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्यों में प्रस्तुत की गयी थी। नवम्बर 2003 की मध्यावधि समीक्षा में की गयी 'घोषणा के अनुसार, बैंकों द्वारा नयी प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्यों के लिए एक परिपत्र जारी किया जिसमें बेंच मार्क मूल उधार दर की गणना के लिए बैंकों द्वारा अपनाये जानेवाले व्यापक मानदंडों को बताया गया था। तब से लगभग सभी वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी पूर्ववर्ती मीयाद से सम्बद्ध मूल उधार दर की प्रणाली के स्थान पर बेंच मार्क मूल उधार दर की घोषणा कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बेंच मार्क मूल उधार दर का दायरा उनके पूर्ववर्ती मूल उधार दर के 10.0 - 12.25 प्रतिशत के दायरे की तुलना में 10.25 - 11.5 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी बेंच मार्क मूल उधार दर की घोषणा करते समय अपनी ब्याज दरों को 25 से लेकर 100 आधार बिन्दुओं तक घटा दिया है। विदेशी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की मूल उधार दर मुखर है, जो मार्च 2003 से 6.75 - 17.5 के व्यापक दायरे से मार्च 2004 तक 10.5 - 14.85 प्रतिशत के दायरे में आ गयी। मार्च 2004 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मांग और मीयादी ऋणों के लिए (जिन पर अधिकतम कारोबार संविदा की जाती है) मध्यम/प्रतिनिधि उधार देने की उधार दर ने जो क्रमशः 11.0 - 12.75 प्रतिशत और 11.0 - 13.25 प्रतिशत के दायरे में रहीं मार्च 2003 के क्रमशः 11.5 - 14.0 प्रतिशत और 12.0 - 14.0 प्रतिशत के तदनुरूपी स्तरों की तुलना में कुछ सुधार दर्शाये।

1.9 इन परिस्थितियों में वर्ष 2003-04 के दौरान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य जोर ऋण की वृद्धि को पूरा करने तथा अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करने और साथ ही लचीली ब्याज दरों को बनाये रखने के साथ-साथ मूल्य स्तर की गतिविधियों पर चौकसीपूर्ण निगाहें रखने पर केन्द्रित रहा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

1.10 वर्ष 2003-04 में मौद्रिक और वित्तीय नीतियों से समर्थित सुदृढ़, व्यापक आर्थिक परिवेश ने वृद्धि की गति को बहाल करने, भारतीय बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन को सुधारने में सहायता की।

कृषि, लघु उद्योग तथा विभिन्न अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों जैसे आवास को ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा अन्य गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर, खुदरा क्षेत्र सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में भी बैंक ऋण में उच्च वृद्धि दर्शायी। निम्न ब्याज दरों के बावजूद ब्याजेतर आय में तेज वृद्धि तथा समग्र व्यय को सीमित करने से बैंकों को हाल के वर्षों में देखे गये लाभ में कुछ वृद्धि दर को बनाये रखने में समर्थ बनाया। वाणिज्यिक बैंकों के परिचालनगत लाभ 2002-03 के 36.3 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 में 29.5 प्रतिशत बढ़े। 2002-03

में दर्ज सुदृढ़ कार्य-निष्पादन के और ऊपर इन बैंकों का निवल लाभ 30.4 प्रतिशत बढ़ा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों के प्रति परिचालनगत लाभ का अनुपात 2002-03 के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 1.1)। यहां यह उल्लेखनीय है कि निवल लाभ में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में सर्वोच्च थी। जिनकी वृद्धि दर 35 पर थी। इसके बाद विदेशी बैंकों और निजी बैंकों का स्थान रहा, जिन्होंने क्रमशः 23 प्रतिशत और 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

सारणी 1.1 : चुनिंदा वित्तीय क्षेत्र के संकेतक : 2002-03 की तुलना में 2003-04

वित्तीय संस्था	संकेतक	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	
1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	क) प्रमुख समुच्चयों में (प्रतिशत) वृद्धि कुल जमाराशियां खाद्येतर ऋण सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	13.4 * 18.6 * 27.3	17.5 18.4 25.1	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) परिचालनगत लाभ निवल लाभ दायरा	2.4 1.0 2.8	2.7 1.1 2.9	
	ग) गैर-निष्पादक आस्ति (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) सकल गैर-निष्पादक आस्तियां निवल गैर-निष्पादक आस्तियां	8.8 4.4	7.2 2.9	
	2. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	क) प्रमुख समुच्चयों में (प्रतिशत) वृद्धि खाद्येतर ऋण ऋण	9.1 4.5	7.5 3.4
		ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) @ परिचालनगत लाभ निवल लाभ दायरा	1.5 -1.1 2.0	1.8 0.6 2.1
		ग) गैर-निष्पादक आस्ति (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) सकल गैर-निष्पादक आस्तियां निवल गैर-निष्पादक आस्तियां	19.0 13.0	17.6 11.1
		3. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	क) प्रमुख समुच्चयों में (प्रतिशत) वृद्धि ¹ Sanctions Disbursements	-31.3 -30.5
ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) ² परिचालनगत लाभ निवल लाभ दायरा			1.4 0.9 0.7	1.3 0.9 0.2
ग) गैर-निष्पादक आस्ति (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) ² निवल गैर-निष्पादक आस्तियां	10.6		—	
4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां³	क) प्रमुख समुच्चयों में (प्रतिशत) वृद्धि सार्वजनिक जमाराशियां		6.8	—
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) निवल लाभ	0.9	—	
	ग) गैर-निष्पादक आस्ति (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) निवल गैर-निष्पादक आस्तियां	2.7	—	

* विलयन के लिए समायोजित @ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित
 1. इसमें आईडीबीआई, आइएफसीआई, आईआईबीआई, आईडीएफसी, सिडबी, आईवीसीएफ, आईसीआईसीआई वेन्चर, टीएफसीआई, एलआईसी, यूटीआई तथा जीआईसी शामिल हैं।
 2. इसमें निम्नलिखित 9 वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईआईबीआई, आईडीएफसी, एक्जिम बैंक, टीएफसीआई, सिडबी, नाबार्ड तथा एनएचबी।
 3. व्यापक में अंतर के साथ रिपोर्ट सूची करनेवाली कम्पनियों के लिए।

1.11 2003-04 में सकल जमाराशियों ने 17.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की, इसके साथ ही मांग जमाराशियों में 32 प्रतिशत और मीयादी जमाराशियों में 15 प्रतिशत की उच्च वृद्धि देखी गयी। बैंकों ने 2003-04 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी आस्तियों का एक बहुत बड़ा भाग बनाये रखना जारी रखा। मार्च 2004 की समाप्ति पर बैंकिंग क्षेत्र ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवल मांग और मीयादी देयताओं के सांविधिक रूप से अपेक्षित न्यूनतम 25 प्रतिशत की तुलना में 41.5 प्रतिशत तक रखा। 'गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों' में निवेशों का अंश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल आस्तियों में गिरा है, जो निजी स्थानन बाजार से संबंधित मानदण्डों के कठोर बनाये जाने को देखते हुए गैर-एसएलआर निवेश का अंश न्यूनतर के फलस्वरूप रहा, संविभागों में मीयादी ऋण घटक सभी बैंक समूह के लिए बढ़ा है और मीयादी जमाराशियों में लगभग 90 प्रतिशत बैठता है जो कि बैंकों की आस्ति-देयता प्रबंधन में सुधार दर्शाता है।

1.12 वर्ष 2003-04 में निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी जमाराशियों में, विशेषकर मांग जमाराशियों में, तेज वृद्धि दर्शायी और इसलिए उनके तुलनपत्र में विस्तार हुआ। तथापि, उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों में तीव्रतम वृद्धि दर्ज की। आय में वृद्धि की दर विदेशी बैंकों के समूहों के लिए उच्चतम थी। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र की नये बैंकों तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का इसी क्रम में स्थान आता है। दूसरी ओर, ब्याज व्यय में आयी गिरावट से मुख्यतया प्रेरित व्यय को सीमित करने के प्रयास सभी बैंक समूहों में देखे गये। गैर-ब्याज आय के बढ़ने की प्रवृत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के मामलों में भी सर्वाधिक उल्लेखनीय रही। तथापि, लेनदेनगत लाभ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ब्याजेतर आय सबसे बड़ा घटक था। वहीं विदेशी बैंकों के ब्याजेतर आय के घटक में शुल्क-आधारित आय ने सबसे बड़ा योगदान किया।

1.13 बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी-अनुपात 2002-03 के 12.7 प्रतिशत से और सुधर कर 2003-04 में 13.0 प्रतिशत हो गया। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए तथा निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंकों के मामले में गिरा। केवल 2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियां 0.5 प्रतिशत जितनी नगण्य बैठती हैं और वे 9.0 प्रतिशत का पूंजी-पर्याप्तता अनुपात पूरा नहीं कर सके।

1.14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल और निवल एनपीए समग्र राशि की दृष्टि से लगातार दूसरे वर्ष भी गिरे हैं, हालांकि उनके निर्धारण का मानदंड बदलकर 90 दिन कर दिया गया। एनपीए में यह गिरावट उनकी वसूली में आयी तेज वृद्धि तथा उनकी नयी आस्तियों में मामूली-सी वृद्धि और खराब आस्तियों को बट्टे में डालने के कारण आयी है। भारी संख्या में प्रावधानों को दर्शाते हुए निवल एनपीए ने भी 2003-04 के

दौरान तेज गिरावट दर्ज की। जहां यह गिरावट सभी बैंक समूह में देखी गयी, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विशेषकर, निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में यह ज्यादा उल्लेखनीय रही, विदेशी बैंकों ने न्यूनतम सकल और निवल एनपीए की स्थिति दर्ज की। बेहतर जोखिम प्रबंधन परम्पराएं, वसूली के बेहतर प्रयासों, सरफेसी अधिनियम 2002 तथा कम्पनी ऋण पुनर्संरचना ने एनपीए के समाधान करने में योगदान किया।

1.15 प्रबंध-तंत्र की सुदृढ़ता के संकेतक के रूप में कुल व्यय के प्रति परिचालन व्यय का अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और विदेशी बैंकों के मामलों में गिरा है, परंतु निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में इनमें मामूली-सी वृद्धि हुई। भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धी दक्षता इस बात से देखी जा सकती है कि उनका यह अनुपात 24 - 35 प्रतिशत के बीच रहा है जो कि 60 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक मार्क से काफी निम्नतर था। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के बाद मानव शक्ति का युक्तिकरण करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वेतन बिलों में तेजी से कटौती हुई है और 2003-04 में यह कुल व्यय का लगभग 17 प्रतिशत बैठता है, तथापि, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए 13 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के लिए केवल 4 प्रतिशत की तुलना में यह अभी भी उच्च बना हुआ है।

सहकारी बैंक

1.16 सहकारी बैंकों ने 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान आस्तियों की उच्चतर वृद्धि दर्शायी। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की संरचना में किए गए परिवर्तनों की नीति ने विशेषकर, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की वृद्धि ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता और लाभप्रदता इन दोनों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ ने 38 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी, जबकि कुछ शहरी सहकारी बैंकों की निवल हानियों में तेजी से गिरावट आयी है। टीयर-I पूंजी 2002-03 के 16 करोड़ रुपये की ऋणात्मक स्थिति से काफी सुधरकर 2003-04 में 256 करोड़ रुपये तक की धनात्मक वृद्धि हुई। टीयर II पूंजी में भी 21 प्रतिशत की संतुलित वृद्धि दर्ज की गयी। गैर-निष्पादक आस्तियों में राशि और प्रतिशत इन दोनों दृष्टियों से गिरावट आयी है।

1.17 ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन क्षमता से निम्न रहा। राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता 2002-03 के दौरान मामूली-सी बढ़ी है। दूसरी ओर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने संपूर्णतया 2002-03 के दौरान हानियां दर्ज करना जारी रखा। ग्रामीण सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादन आस्तियां उच्च बनी रहीं - मध्यवर्ती सरकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में उच्चतर स्तर की थीं।

वित्तीय संस्थाएं

1.18 दो वर्षों के अंतराल के बाद, 2003-04 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता की वृद्धि में गिरने की प्रवृत्ति पलट गयी। यह उल्लेखनीय है कि जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी मीयादी ऋणदात्री ऋण संस्था के रूप में उभरी है तथा इसका कुल वितरण आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईडीएफसी और आईआईबीआई के मिले-जुले संवितरणों से भी अधिक हो गया है। तथापि प्रमुख अखिल वित्तीय संस्थाओं से संसाधनों का निवल प्रभाव चुकौती के लिए सकल बहिर्वाह को समायोजित करने के बाद ऋणात्मक बना रहा, जिसमें बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, मंद पूंजी बाजार जो संसाधन संग्रहण के प्रयासों में बाधक बन रहा था, और कम्पनियों के लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता के साथ परिचालन के परिवेश में परिवर्तन, गैर-निष्पादक आस्तियों का निरन्तर बने रहना तथा संघटनात्मक पुनर्संरचना का जो दबाव इन संस्थाओं पर पड़ रहा है, उसने अन्य बातों के साथ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए कारोबार के अंश में गिरावट ला दी।

1.19 एक समूह के रूप में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के तुलनापत्र ने 2002-03 के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। देयताओं के घटकों में व्यापक प्रवृत्तियां लगभग वही बनी रहीं जिनमें बांड और डिबेंचर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की देयताओं का लगभग आधा भाग बनता है। तथापि, आस्ति पक्ष में उसकी संरचना ऋण और अग्रिमों से बदलकर निवेशों और अधिक तरल आस्तियों की धारिता के रूप में हो गयी। वित्तीय संस्थाओं की आय और उनके व्यय दोनों ने गिरने की प्रवृत्ति दर्शायी जिससे वित्तीय संस्थाओं के लाभप्रदता अनुपात अपरिवर्तनीय बने रहे। जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात आईएफसीआई और आईआईबीआई को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए काफी उच्च स्तर पर बना रहा, जबकि आईएफसीआई और आईआईबीआई के लिए उनकी आस्ति-गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आयी और पूंजी आधार क्षीण हुआ। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के निवल एनपीए 2003-04 के दौरान बढ़े हैं, जो मानक आस्तियों में क्षरण और परियोजनाओं की लागत बढ़ने के कारण रहा।

1.20 पारस्परिक निधियों द्वारा साधन संग्रहण 2003-04 के दौरान दस गुने से भी ज्यादा बढ़ा है। जहां निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों ने उच्च स्तरीय वृद्धि दर्ज की, यूटीआई ने भी इस बदलाव को झेला और उसने सकारात्मक संग्रहण की सूचना दी। पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधनों का संग्रहण मुख्य रूप से ऋणोन्मुखी पारस्परिक निधियों के कारण था।

गैर-बैंकिंग वित्तीय बैंकिंग

1.21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या में लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट आयी जो इन कम्पनियों के सम्मेलन, बन्द होने तथा

लाइसेंस रद्द होने को दर्शाता है। जनता से जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कम्पनियों की संख्या भी गिरी है जो सम्मेलनों, उनके बन्द होने और लाइसेंसों के रद्द होने को भी दर्शाती है, जमाराशियां स्वीकृत करनेवाली कम्पनियों की संख्या भी कम हुई है क्योंकि उनको जनता से जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली गतिविधियों में बदल दिया गया है। यदि आस्तियों के गतिविधि-वार वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र की व्यापक स्थिति 2002-03 के दौरान कमोवेश वैसी ही रही। हालांकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्तियों में मामूली-सी गिरावट आयी है, परंतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पास रखी उनकी सार्वजनिक जमाराशियों, विनियामक पर्यवेक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने में मामूली-सी वृद्धि देखी गयी जो क्षेत्रीय संकेन्द्रण के घटने और उन्हें दिये गये निम्न ब्याज दरों के कारण था। विवेक-सम्मत संकेतकों की दृष्टि से केवल कुछ सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (6.3 प्रतिशत) 12 प्रतिशत का निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर प्राप्त करने में सफल रहीं। वास्तव में उनमें तीन-चौथाई कम्पनियों ने 30 प्रतिशत से अधिक का सीआरएआर सूचित किया। यद्यपि सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में तेजी से गिरावट की सूचना दी गयी है, फिर भी निम्नतर प्रावधानीकरण का आश्रय लेने का कारण सितम्बर 2003 के अंत में उनकी निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में मामूली-सी वृद्धि देखी गयी।

1.22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन की पिछले 2 वर्षों के दौरान देखी गयी हानियों की स्थितियां वर्ष 2002-03 के दौरान बदल गयीं। आय में यह गिरावट व्यय में हुई गिरावट की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इसका मुख्य कारण था - ब्याज दरों में कमी के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के ब्याज व्ययों में तेजी से गिरावट का आना। आय के घटकों में शुल्क आधारित आय मामूली-सी बढ़ी, यद्यपि यह उनकी आय का एक छोटा-सा भाग (7.4 प्रतिशत) बना रहा।

1.23 सरफेसी अधिनियम 2002 के अधिनियम बनने, वित्तीय कम्पनी विनियमन विधेयक की शुरुआत होने तथा विकास वित्त संस्थाओं पर कार्यकारी दल की चर्चाओं का गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के कार्यकारण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2004-05 के दौरान गतिविधियां

1.24 व्यापक आधारवाली वृद्धि की गति 2004-05 की पहली तिमाही में भी जारी रही। 7.4 प्रतिशत की सकल देशी उत्पाद वृद्धि 2003-04 की पहली तिमाही में दर्ज की गयी वृद्धि के ऊपर लगभग 2 प्रतिशत बिन्दु उच्चतर थी। निर्माण तथा कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में, 6 से 11 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि बनी रही। कृषि क्षेत्र ने 2003-04 की

पहली तिमाही के 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2004-05 की पहली तिमाही में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पाद 2003-04 के तदनुसूची स्तरों की तुलना में 2004-05 में निम्न होने की आशा है तथापि, रबी फसल का उत्पादन अनुकूल होने की आशा है। मौसमी (जून-सितम्बर) वर्षा 36 मौसमी उप-मण्डलों से 23 में अधिक / सामान्यतः थी और शेष 13 उप-मण्डलों में कम वर्षा दर्ज की गयी। जहाँ मौसमी जिलों के 56 प्रतिशत हिस्सों में अधिक/ सामान्य वर्षा हुई, शेष 44 प्रतिशत भागों में कम या / छिटपुट वर्षा हुई। जहाँ भावी सम्भावनाएं अभी भी अस्पष्ट हैं, वहीं वर्तमान आकलन यह स्पष्ट संकेत करता है कि शायद पहले अनुमानित 3.0 प्रतिशत की कृषि की वृद्धि पूरी नहीं हो। जैसा कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक द्वारा संकेत किया गया औद्योगिक वृद्धि ने अप्रैल-अगस्त 2004 के दौरान 7.9 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की, जबकि अप्रैल-अगस्त 2003 के दौरान इसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बुनियादी माल, पूंजीगत माल, अर्ध-निर्मित माल, उपभोक्ता टिकाऊ माल के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि बने रहने के संकेत हैं। इस प्रकार औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि की संभावना में सुधार हुआ है। इसके अलावा निर्यातों में उछाल बना रहा और उन्होंने अप्रैल-सितम्बर 2004 के दौरान अमरीकी डालर की दृष्टि से 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि अप्रैल-सितम्बर 2003 के दौरान इसमें 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जहाँ पहली तिमाही के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के सदेउ के अनुमान पूरे राजकोषीय वर्ष के लिए पहले प्रायोजित 6.5 से 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के अनुरूप है, वहीं देश के कुछ भागों में कम वर्षा और खरीफ की फसल पर उसका प्रभाव, वृद्धि की सम्भावना पर निम्नमुखी प्रभाव डाल सकते हैं, इसके अलावा, उच्चतर तेल मूल्यों का सदेउ की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि की बेहतर सम्भावनाएं तथा निर्यातों में निरन्तर उछाले की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने की आशा है। कुल मिलाकर, तस्वीर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हैं अतः यह उचित होगा कि 2004-05 के दौरान सदेउ की समग्र वृद्धि को 6.5 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत के दायरों में रखा जाए। यह मानते हुए कि उच्च तथा अनिश्चित तेल-मूल्यों का मिला जुला निम्नतर जोखिम तथा अन्तर्राष्ट्रीय चलनिधि परिवेश में अचानक बदलाव प्रबन्धन योग्य बने रहेंगे।

1.25 2004-05 में मुद्रा आपूर्ति 29 अक्टूबर 2004 तक 6.46 प्रतिशत (1,32,428 करोड़ रु.) रूपांतरण के प्रभाव को घटाकर 6.4 प्रतिशत (रु.1,28,859 करोड़) की निम्नतर दर से बढ़ी है, जबकि 2003-04 की तदनुसूची अवधि में इसमें 8.9 प्रतिशत (1,53,474 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई थी। तथापि, वार्षिक आधार पर एम 3 में 13.9 प्रतिशत (रूपांतरण प्रभाव को घटाकर 13.9 प्रतिशत) की वृद्धि 2003-04 के दौरान 12.1 प्रतिशत की वृद्धि से उच्चतर रही। थोक मूल्य

सूचकांक में आये घट-बढ़ द्वारा मापे गये अनुसार बिन्दु-दर-बिन्दु आधारपर वार्षिक मुद्रास्फीति मार्चात की 4.6 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2004 के अंत तक 8.7 प्रतिशत हो गयी थी, 30 अक्टूबर 2004 तक गिरकर 7.1 प्रतिशत पर आ गयी। औसत आधार पर थोमूसू पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति 30 अक्टूबर 2004 को 6.3 प्रतिशत थी, जबकि 2003 की तदनुसूची अवधि में यह 5.0 प्रतिशत थी। जबकि थोमूसू पर आधारित मुद्रास्फीति में अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों तथा धातु मूल्यों में वृद्धि के कारण तीव्र वृद्धि हुई है, वहीं उ.मू.सू. मुद्रास्फीति में मामूली-सी वृद्धि हुई है। वार्षिक औसत आधार पर उ.मू.सू. में दर्शाये गये अनुरूप मुद्रास्फीति सितंबर 2004 में 3.6 प्रतिशत थी, जबकि 2002-03 में यह 3.9 प्रतिशत थी। तथापि उ.मू.सू. की मुद्रास्फीति पर थो.मू.सू. की मुद्रास्फीति का प्रमाण कुछ समय के अन्तराल पर दिखाई देता है। चालू आकलन पर, यह मानते हुए कि अब आगे कोई आपूर्ति आघात नहीं होगा, और चलनिधि की स्थिति प्रबंधन-योग्य बनी रहेगी। वर्ष 2004-05 के लिए थो.मू.सू. पर आधारित बिन्दु-दर-बिन्दु वर्षान्त मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी, जबकि मई 2004 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

1.26 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियों में वृद्धि दर 29 अक्टूबर 2004 तक 7.5 प्रतिशत (रूपांतरण के घटाकर 7.2 प्रतिशत) पर निम्नतर थी, जबकि 2003-4 तदनुसूची अवधि में यह 9.0 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण बैंकिंग प्रणाली में अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों में कमी का आना था। तथापि, वार्षिक आधार पर 15.8 प्रतिशत रूपांतरण को घटाकर 15.8 प्रतिशत (रूपांतरण के प्रभाव को घटाकर 15.6 प्रतिशत) पर कुल जमाराशियों में वृद्धि 2003-04 में हुई 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले उच्चतर थी। 2004-05 के दौरान (29 अक्टूबर 2004 तक) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 17.5 प्रतिशत (1,47,491 करोड़ रु.) [13.7 प्रतिशत (1,14,809 करोड़ रु.) के रूपांतरण को घटाकर] की वृद्धि हुई जो कि तदनुसूची अवधि में हुई 4.5 प्रतिशत (33,088 करोड़ रु.) की वृद्धि से उच्च थी। खाद्य ऋण में 2003-04 में 13,459 करोड़ रु. की गिरावट के विपरीत 3,751 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जो लगभग 17,210 करोड़ रु. की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि के दौरान खाद्येतर ऋण ने 2003-04 की तदनुसूची अवधि में 6.8 प्रतिशत (46,539 करोड़ रु.) की वृद्धि की तुलना में 17.9 प्रतिशत (1,43,741 करोड़ रु.) [13.8 प्रतिशत (रु. 1,11,059 करोड़)] की भारी वृद्धि दर्ज की। वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 2003-04 की तदनुसूची अवधि में 40.4 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान (29 अक्टूबर 2004 तक) 127.8 प्रतिशत पर काफी उच्चतर थी। बैंकों से उपलब्ध ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन पर विस्तृत सूचना यह स्पष्ट करती है कि 2004-05 के दौरान (सितम्बर

2004 तक) ऋण प्रवाह का दो-तिहाई से अधिक भाग खुदरा, आवास तथा अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋणों के कारण था। विस्तार तथा उत्पादन योजनाओं में विस्तार के प्रमाण के साथ 2004-05 में निवेश गतिविधियों में पुनः सक्रियता देखी गयी। अतः, उद्योग की ऋण आवश्यकताओं में और गति आने की सम्भावना है।

1.27 हाल के वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमानित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश 25 प्रतिशत की निर्धारित एसएलआर अपेक्षा से काफी अधिक रहे हैं। मार्च 2004 के अंत में एसएलआर प्रतिभूतियों में 2,67,328 करोड़ रु.के अतिरिक्त निवेश बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 16.3 प्रतिशत बनते हैं। तथापि, 2004-05 के अनुसार (29 अक्टूबर 2004 तक) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 28,955 करोड़ रु. (रुपांतरण प्रभाव को घटाकर) के निवेश 2003-04 की तदनुसूची अवधि के 84,031 करोड़ रु. के निवेशों से कम थे जिनका आंशिक कारण था ऋण की मांग में तेजी का आना। परिणामतः वाणिज्यिक बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता 2004-05 (29 अक्टूबर 2004 तक) घटकर 2,59,083 करोड़ रुपए अथवा निवल मांग और मीयादी देयताओं ता 14.5 प्रतिशत रह गयी। चूंकि 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा मांग उच्च रहने की संभावना है इसलिए बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की निम्नतर मांग का सरकार के बाजार उधार कार्यक्रमों के लिए निहितार्थ है।

1.28 2004-05 के दौरान (अप्रैल से 31 अक्टूबर 2004 तक) वित्तीय बाजार आम तौर पर स्थिर बने रहे, यद्यपि ब्याज दरों में, विशेषकर दीर्घावधि ब्याज दरों में कुछ ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गयी। औसत मांग मुद्रा दर, 91 दिवसीय, और 364 दिवसीय खजाना बिल की दरों तथा सरकारी एक वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर आय ने ऊर्ध्वमुखी परिवर्तन दर्शाया। 61 से 90 दिन की परिपक्वतावाले वाणिज्यिक पत्रों पर भारत औसत बड़ा दर अप्रैल के 5.1 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2004 के अंत तक 5.4 प्रतिशत हो गयी। इसी अवधि में दैनिक मात्रा में बाजार रिपो दर 3.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत हो गयी। तीन माह के जमा प्रमाणपत्रों पर विशेष ब्याज दर अप्रैल 2004 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर मध्य अक्टूबर 2004 तक 4.8 प्रतिशत हो गयी। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक वर्ष से अधिक के जमा दरों को 5.0-6.0 प्रतिशत से घटाकर 4.8 -5.8 कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की बेंचमार्क मूल उधारी दर 10.3 -11.00 प्रतिशत तथा 11.0 - 13.0 प्रतिशत के दायरे में थी। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधारी दर अप्रैल 2004 के 10.5 - 13.0 प्रतिशत के दायरे से घटकर अक्टूबर 2004 तक 9.8 - 13.0 प्रतिशत

के दायरे में आ गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मांग और मीयादी देयताओं पर प्रातिनिधिक (मध्यम) उधार दरें (जिस पर अधिकतम कारोबार किया जाता है) सितंबर 2004 में 8.25-12.5 के दायरे में रहीं, जबकि मार्च 2004 में ये 11.0-12.8 प्रतिशत के दायरे में थीं।

1.29 बाह्य क्षेत्र की दृष्टि से 2004-05 की पहली छमाही में वणिक व्यापार में वृद्धि तेज रही है और वह वर्ष के लिए निर्धारित अमरीकी डालर की दृष्टि से 16 प्रतिशत के लक्ष्यों के काफी ऊपर रही। अप्रैल-सितम्बर 2004 के दौरान भारत के निर्यात अमरीकी डालर की दृष्टि से 24.4 प्रतिशत बढ़े, जबकि 2003-04 की तदनुसूची अवधि में यह वृद्धि 8.1 प्रतिशत थी। आयातों में 34.3 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर रही, जबकि 2003-04 की तदनुसूची अवधि में इनमें 21.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तेल आयात पिछले वर्ष के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 57.8 प्रतिशत की दर से बढ़े जबकि तेल इतर आयात 27.4 प्रतिशत की तुलना में 25.8 प्रतिशत बढ़े। समग्र व्यापार घाटा 2003-04 की तदनुसूची अवधि के 7.4 बिलि.अ.डा.से बढ़कर 2004-05 में 12.7 बिलि.अ.डा.का हो गया। इस वर्ष उच्चतर व्यापार घाटे का अधिकांश भाग तेल आयातों के उच्चतर बिलों को दर्शाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बढ़ने तथा आयात की मांग में वृद्धि के कारण हैं, जो उच्चतर पूंजीगत माल के आयातों के रूप में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से उत्पन्न हुई है। 2004-05 की पहली छमाही के दौरान बढ़ता हुआ व्यापार घाटा अदृश्य मदों के अंतर्गत हुई अधिशेष द्वारा समायोजित राशि से अधिक रहा, जिससे चालू खाता अधिशेष बढ़ा। 2004-05 की पहली तिमाही में निवल पूंजी प्रवाह 5.6 बिलियन अमरीकी डालर का रहा जो कि 2003-04 की पहली तिमाही में दर्ज 6 बिलियन अमरीकी डालर के आगम से तुलनीय है। 2004-05 राजकोषीय वर्ष में निवल पूंजी आगम मुख्य रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वाणिज्यिक उधारों, अल्पावधि व्यापार ऋणों के कारण रहा। इसके फलस्वरूप अप्रैल-जून 2004 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 7.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अर्जन हुआ।

1.30 इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में, वर्ष 2004-05 की पहली छमाही के दौरान वर्ष 2004-05 के उत्तरार्ध के लिए समग्र मौद्रिक नीति का बल इस प्रकार होगा : (i) मूल्य स्थिरता पर समान बल देते हुए अर्थव्यवस्था में ऋणों की वृद्धि को पूरा करने तथा निवेश और निर्यात मांग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त चल निधि का प्रावधान करना; (ii) उपर्युक्त के अनुरूप, एक ऐसे ब्याज दर परिवेश का अनुसरण करना जो व्यापक आर्थिक स्थिति और मूल्य स्थिरता तथा वृद्धि की गति को बनाये रखने के अनुकूल हो; (iii) मुद्रास्फीतिगत आशंकाओं को स्थिर रखने की दृष्टि से, बनती हुई परिस्थितियों में, एक सुनियोजित ढंग से इसके उपायों पर विचार करना।